GEO IAS
It's about quality

4 July 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | PIB | PIB | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 4 July 2024

Important News Articles

1. 16वें वित्त आयोग (FC) को समेकित निधि के हस्तांतरण का कार्य सौंपा: द हिन्दू
2. डिजिटल इंडिया पहल के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे हुए - पीएम इंडिया
3. भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सामरिक संबंध - लोकमत टाइम्स
4. फ्रांस हरित विकास में भारत का स्थायी साझेदार - द हिन्दू
5. उत्तर प्रदेश के हाथरस में धार्मिक सभा में भगदड़ की घटना: द हिन्दू
6. एरियन 6 ने लॉन्च किया LIFI - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी
7. प्रदूषण के स्तर में वृद्धि से स्वच्छ हवा वाले शहरों में मृत्यु दर बढ़ सकती है: अध्ययन - द हिंदू
8. स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक बढ़ाया - द हिंदू

Editorials, Gists and Explainers

9. पेट्रोरसायन की औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के विकास में भूमिका – द मिंट
10. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 816 मिलियन डॉलर बढ़कर 653.7 बिलियन डॉलर हुआ – इकोनॉमिक टाइम्स
11. RBI का अधिशेष: खर्च करें या न करें - इंडियन एक्सप्रेस

Quick Look

1. भारत ने कोलंबो प्रक्रिया के तहत अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं – इकोनॉमिक टाइम्स
2. मेगाफौना: आंध्र प्रदेश में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला मिला

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. 16वें वित्त आयोग (FC) को समेकित निधि के हस्तांतरण का कार्य सौंपा: द हिन्दू

प्रासंगिकता:
जीएस II - संवैधानिक निकाय: वित्त आयोग

प्रीलिम्स टेकअवे
- वित्त आयोग

प्रसंग:
- 16वें वित्त आयोग (FC) को समेकित निधि के हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया है तथा अनुच्छेद 280 और 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं को सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है।

वित्त आयोग क्या है?
- भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बनाई गई एक संवैधानिक इकाई है। इसकी मुख्य भूमिका केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन पर सलाह देना है। 27 नवंबर 2017 को स्थापित, पंद्रहवें वित्त आयोग ने अंतरिम और अंतिम दोनों रिपोर्टों के माध्यम से 1 अप्रैल 2020 से छह साल के लिए सिफारिशें प्रदान कीं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक वैध हैं।

भारतीय वित्त आयोग (FCI) की संरचना:
- संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चार सदस्य होते हैं।
- कार्यकाल: अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट अवधि; सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

योग्यताएं:
- अध्यक्ष: सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना चाहिए।
- सदस्य: इसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या एक योग्य व्यक्ति, एक वित्त/लेखा विशेषज्ञ, एक अनुभवी वित्तीय प्रशासक और एक अर्थशास्त्री शामिल होना चाहिए।

कार्य:
- टैक्स वितरण: यह सिफारिश करता है कि टैक्स आय को केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए।
- सहायता अनुदान: केंद्र से राज्यों को अनुदान के सिद्धांतों पर सलाह देना।
- राज्य निधि: पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य निधि बढ़ाने के उपाय सुझाए गए।
- अन्य मामले: राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित अतिरिक्त मुद्दों पर विचार किया जाता है।

प्रतिवेदन:
- रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो इसके बाद इसे की गई कार्रवाई पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ संसद में प्रस्तुत करते हैं।

16वें वित्त आयोग के बारे में:
- अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं ।

16वें वित्त आयोग के लिए मुख्य विचारणीय विषय:
- टैक्स आय का विभाजन: राज्य के हिस्से सहित संघ और राज्यों के बीच कर वितरण की सिफारिश करना।
- सहायता अनुदान के सिद्धांत: भारत की समेकित निधि से राज्यों को अनुदान के लिए सिद्धांत स्थापित करना, विशेष रूप से अनुच्छेद 275 के अंतर्गत।
- स्थानीय निकायों के लिए राज्य निधि में वृद्धि: राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य निधि में वृद्धि के उपाय सुझाएँ।
- आपदा प्रबंधन वित्तपोषण का मूल्यांकन: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन वित्तपोषण की समीक्षा करना और सुधार की सिफारिश करना।

16वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए सिफारिशें:

15वें वित्त आयोग के सिद्धांतों पर पुनः विचार करें:
- राज्य GST से जुड़े संपत्ति कर संग्रह को बढ़ाया जाएगा।

- खातों के रखरखाव में सुधार करें।
- प्रदूषण निवारण के लिए संसाधन आवंटित करें।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल पर ध्यान केंद्रित करें।
- भारत के गतिशील शहरीकरण को स्वीकार करें।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि शहरी क्षेत्रों में अंतर-सरकारी स्थानान्तरण कम से कम दोगुना हो।

2. डिजिटल इंडिया पहल के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे हुए - पीएम इंडिया

प्रासंगिकता:
जीएस III - वित्तीय समावेशन

प्रीलिम्स टेकअवे
- डिजिटल इंडिया मिशन

प्रसंग:
- प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया पहल के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे होने की सराहना की तथा 'जीवन की सुगमता' और पारदर्शिता बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

डिजिटल इंडिया पहल क्या है?
- वर्ष 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रमुख केंद्रित क्षेत्र:
- डिजिटल बुनियादी ढांचा
- शासन
- मांग पर सेवाएं
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भूमिका:
- ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटना: भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और पहुंच का विस्तार करना , प्रौद्योगिकी पहुंच के अंतर को पाटना।
- वित्तीय समावेशन: मोबाइल और आधार से जुड़ी भुगतान प्रणालियाँ, डिजिटल इंडिया के तहत DBT योजनाएँ नकदी रहित लेनदेन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाती हैं, जिससे डिजिटल वित्तीय समावेशन का विस्तार होता है। भारत में सभी भुगतानों में से 40% से अधिक भुगतान डिजिटल हैं।
- सुलभ डिजिटल सेवाएँ: डिजिटल लॉकर, ईसाइन फ्रेमवर्क और ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाते हैं।
- सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता: डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहल का उद्देश्य हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को ई-साक्षर बनाना है। "स्वयं" और "राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी" जैसे कार्यक्रम ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करते हैं।
- रोजगार के अवसर: डिजिटल बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में वृद्धि से छोटे शहरों सहित अन्य स्थानों पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा होते हैं।
- मोबाइल कनेक्टिविटी और ऐप्स: यह पहल सरकारी सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप्स को बढ़ावा देती है, जिससे पहुंच और सुविधा बढ़ती है, जैसे उमंग ऐप।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सीमाएँ:
- डिजिटल डिवाइड: प्रगति के बावजूद, डिजिटल डिवाइड कायम है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच सीमित है। लगभग 50% आबादी अभी भी ऑनलाइन नहीं है।
- अनुकूलन का अभाव: विभिन्न क्षेत्रों में अपनाने की तत्परता में उच्च विविधता के कारण सभी के लिए एक जैसा दृष्टिकोण अपनाने के बजाय कार्यान्वयन में लचीलेपन की आवश्यकता होती है।
- डिजिटल कौशल विकास की सफलता में भिन्नता: योग्य प्रशिक्षकों, स्थानीय भाषा की विषय-वस्तु और निगरानी तंत्र की कमी के कारण डिजिटल साक्षरता पहल समान रूप से सफल नहीं हो पाती है।
- सामर्थ्य संबंधी बाधाएं: उपकरणों और डेटा योजनाओं की उच्च लागत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्थायी अपनाने को बाधित करती है।
- ग्रामीण अवसंरचना अंतराल: अपर्याप्त बिजली और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों में इसे अपनाने में बाधा डालते हैं, भले ही शहरी क्षेत्र 5 जी और फाइबराइजेशन की ओर अग्रसर हों ।

आगे की राह:

- बुनियादी ढांचे का विकास: व्यापक ग्रामीण ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचे में निवेश करें, उदाहरण के लिए, भारतनेट परियोजना का लक्ष्य 250,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है।
- लक्षित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में कार्यक्रम शुरू करना, जैसे राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: डिजिटल समावेशन के लिए सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, उदाहरण के लिए, 'डिजिटल गांव' परियोजनाएं।
- सब्सिडीकृत योजनाएं: आर्थिक रूप से वंचित आबादी को लागत प्रभावी स्मार्टफोन और डेटा योजनाएं प्रदान करना।
- प्रभाव आकलन: विभिन्न जनसंख्या वर्गों पर डिजिटल पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए नियमित सर्वेक्षण और फीडबैक तंत्र।
- बहुभाषी डिजिटल पहल: क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री का विकास और प्रचार-प्रसार।

निष्कर्ष:

- हालांकि डिजिटल इंडिया ने इसकी नींव रख दी है, लेकिन समग्र डिजिटल सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए धैर्यवान हितधारकों को केवल संख्याओं के पीछे भागने के बजाय सतत मॉडलों के माध्यम से जनसांख्यिकीय और क्षेत्रीय वास्तविकताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।

3. भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सामरिक संबंध - लोकमत टाइम्स

प्रासंगिकता:

जीएस II - भारत और उसके पड़ोसी, द्विपक्षीय समूह और समझौते

प्रीलिम्स टेकअवे

- भारत बांग्लादेश संबंध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देश आर्थिक संबंधों को व्यापक बनाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए।

हालिया बैठक के प्रमुख परिणाम:

- CEPA की शुरूआत: भारत और बांग्लादेश आर्थिक संबंधों को बढ़ाने तथा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए CEPA पर काम शुरू करने पर सहमत हुए।
- रसद और व्यापार प्रवाह: भारत बांग्लादेश के सिराजगंज में एक अंतर्देशीय कंटेनर बंदरगाह के निर्माण का समर्थन करेगा।
- गंगा जल संधि का नवीकरण: दोनों देश वर्ष 1996 की गंगा जल संधि को नवीकृत करने के लिए तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू करेंगे, जिसमें बाढ़ प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और पेयजल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- समुद्री सहयोग समझौता: हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों को प्रतिबिंबित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के निर्णय का भारत द्वारा स्वागत किया गया।

भारत-बांग्लादेश सहयोग में अन्य हालिया घटनाक्रम:

- भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन: ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए उद्घाटन किया गया।
- वर्ष 1965 से पूर्व के रेल संपर्कों का पुनर्वास: भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1965 से पूर्व के कई रेल संपर्कों का पुनर्वास किया गया है और वे अब चालू हैं।
- अखौरा -अगरतला रेल संपर्क: त्रिपुरा के माध्यम से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला यह छठा भारत-बांग्लादेश सीमा पार रेल संपर्क है।
- परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान: भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड में प्रमुख परिवहन परियोजनाओं को जोड़ता है, एक शिपिंग नेटवर्क स्थापित करता है।
- मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट: ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए परिचालन।
- खुलना-मोंगला पोर्ट कार्गो सुविधा: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्गो आवाजाही को सुविधाजनक बनाती है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र जैसे केंद्रों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।
- ITEC प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति: बांग्लादेश को भारत में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और छात्रवृत्तियों से लाभ मिलता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध:

ऐतिहासिक संबंध:

- वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान यह संबंध और मजबूत हुआ, जब भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण सैन्य और भौतिक सहायता प्रदान की।
- सैन्य शासन और भारत विरोधी भावनाओं के उदय के कारण संबंध बिगड़ गए, लेकिन वर्ष 1996 में गंगा जल बंटवारे पर संधि के बाद संबंध स्थिर हो गए।

आर्थिक सहयोग:

- पिछले दशक में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तथा भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
- भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेशी निर्यात लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का होगा।
- वर्ष 2010 से भारत ने बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की ऋण सहायता प्रदान की है।

ऊर्जा:

- बांग्लादेश भारत से लगभग 2,000 मेगावाट (MW) बिजली आयात करता है।
- 2018 में, रूस, बांग्लादेश और भारत ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना, बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिए सहयोग पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

4. फ्रांस हरित विकास में भारत का स्थायी साझेदार - द हिन्दू

प्रासंगिकता:
जीएस II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रीलिम्स टेकअवे

- भारत फ्रांस संबंध

प्रसंग:

- वर्ष 2023 में, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री ने 'ग्रह के लिए साझेदारी' को भारत-फ्रांस क्षितिज 2047 रोडमैप के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में ऊंचा किया।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2023 में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी।

इंडो-फ्रेंच होराइजन 2047 के स्तंभ:

- सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी
- ग्रह के लिए साझेदारी
- लोगों के लिए साझेदारी
- पर्यावरणीय स्थिरता के लिए साझेदारी

वर्ष 2023 में भारत और फ्रांस के बीच चार पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें शामिल हैं:

- राजस्थान में एक परियोजना का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना, वन्यजीव स्थितियों में सुधार लाना तथा स्थानीय आजीविका को समर्थन देना है।
- हिमाचल प्रदेश के छोटे शहरों में स्वच्छता में सुधार के लिए एक पहल।
- भारत के प्रमुख परिपत्र अर्थव्यवस्था कार्यक्रम, CITIIS के हिस्से के रूप में 18 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक परियोजना।
- इलेक्ट्रिक बसों और ऊर्जा कुशल आवास के वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ हरित ऋण लाइन।

भारत और फ्रांस संबंधों की प्रमुख विशेषताएं:

- सामरिक भागीदारी: भारत के वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद, फ्रांस भारत के साथ सामरिक वार्ता शुरू करने वाला पहला देश था और उसने भारत की सुरक्षा संबंधी मजबूरियों को समझते हुए द्विपक्षीय प्रतिबंध नहीं लगाए। फ्रांस पहला पश्चिमी देश था जिसके साथ भारत ने सामरिक भागीदारी पर हस्ताक्षर किए।
- आर्थिक: भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2022-23 में 13.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022-23 में 659.77 मिलियन डॉलर के FDI प्रवाह के साथ फ्रांस भारत में एक महत्वपूर्ण निवेशक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, फ्रांस को भारतीय निर्यात कुल 3.06 बिलियन डॉलर था, जबकि फ्रांस से आयात 2.36 बिलियन डॉलर था।

- रक्षा : वार्षिक रक्षा वार्ता (रक्षा मंत्री स्तर) और रक्षा सहयोग पर उच्च समिति (सचिव स्तर) के तहत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाती है। P-75 स्कॉर्पीन डील वर्ष 2005 और राफेल जेट की खरीद गहरे रक्षा संबंधों को उजागर करती है। नियमित संयुक्त रक्षा अभ्यासों में गरुड़ (वायु सेना), शक्ति (सेना) और वरुण (नौसेना) शामिल हैं।
- अंतरिक्ष: इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) के बीच अंतरिक्ष में सहयोग 50 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। फ्रांस भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए घटकों और उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
- ऊर्जा सहयोग: जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (JNPP) और लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) तथा उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों (AMR) पर साझेदारी से संबंधित चर्चाओं में प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था।
- शिक्षा: लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में हैं, और वर्ष 2018 में डिग्री की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2023 में, वर्ष 2030 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या 30,000 तक बढ़ाने पर सहमति हुई।
- फ्रांस में समुदाय: मुख्य भूमि फ्रांस में लगभग 119,000 भारतीय समुदाय के सदस्य रहते हैं, जो मुख्य रूप से पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों और तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों से हैं।
- पर्यटन: वर्ष 2019 में करीब 250,000 फ्रांसीसी पर्यटक भारत आए, जिनमें राजस्थान सबसे लोकप्रिय गंतव्य रहा। वहीं, करीब 700,000 भारतीय फ्रांस गए ।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन: फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है और MTCR, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के प्रवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। फ्रांस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के लिए भारत की बोली और संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT) को अपनाने का समर्थन करना जारी रखता है।

सामान्य अध्ययन III

5. उत्तर प्रदेश के हाथरस में धार्मिक सभा में भगदड़ की घटना: द हिन्दू

प्रीलिम्स टेकअवे
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथ्य

प्रासंगिकता:
जीएस II - शासन

प्रसंग:
- हाथरस में एक धार्मिक सभा में भगदड़ के कारण 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले की घटनाओं में कालकाजी मंदिर का मंच ढहना और वर्ष 2022 में वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ शामिल है।

स्टेम्पेड (भगदड़) क्या है?
- भगदड़ भीड़ की आवाजाही में व्यवधान पैदा करती है, जिसके कारण चोट और मौतें होती हैं। इसमें योगदान देने वाले कारकों में खराब इवेंट मैनेजमेंट, भीड़भाड़ या अचानक भारी बारिश, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं।

निवारक उपाय:
- उचित जोखिम विश्लेषण और क्षमता नियोजन में घटना की आवृत्ति, मौसम और इलाके को ध्यान में रखना चाहिए। सुरक्षा प्रोटोकॉल में कई प्रवेश और निकास बिंदु, आपातकालीन चिकित्सा कर्मी, प्राथमिक चिकित्सा किट और एम्बुलेंस शामिल होने चाहिए।

भीड़ प्रबंधन पर NDMA दिशानिर्देश:
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने सामूहिक समारोहों में जोखिम को रोकने और कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मुख्य दिशानिर्देश:
- जोखिम मूल्यांकन और योजना: भूमिकाओं, संचार प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हुए एक भीड़ प्रबंधन योजना विकसित करें।
- बुनियादी ढांचा और सुविधाएं: पर्याप्त स्थान, प्रवेश/निकास बिंदु, संकेत, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता सुनिश्चित करें।
- भीड़ प्रवाह प्रबंधन: भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने और जोखिमों की पहचान करने के लिए CCTV और ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करें, तथा भीड़ की सहायता के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की भी व्यवस्था करें।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया: भगदड़, आग, चिकित्सा समस्याओं या आतंकवादी हमलों जैसी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहें, सुनिश्चित करें कि चिकित्सा सुविधाएं और प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हों।

- प्रशिक्षण और जागरूकता: आयोजकों, सुरक्षाकर्मियों और स्वयंसेवकों को भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षित करें।
- प्रौद्योगिकियों का उपयोग: भीड़ की भविष्यवाणी और व्यवहार विश्लेषण के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करें।

6. एरियन 6 ने लॉन्च किया LIFI - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी

प्रासंगिकता:
जीएस III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रीलिम्स टेकअवे
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथ्य

प्रसंग:
- रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल के तहत भारतीय नौसेना के सामने आने वाली संचार चुनौतियों से निपटने के लिए Li-Fi प्रौद्योगिकी को अपनाया है।

लाइट फिडेलिटी (Li-Fi) प्रौद्योगिकी के बारे में:
- Li-Fi एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है, पारंपरिक Wi-Fi के विपरीत जो रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। यह उच्च गति, सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल संचार चैनल बनाने के लिए LED का उपयोग करता है।

कार्य प्रणाली:
- डेटा ट्रांसमीटर के रूप में LED: LED डेटा को एनकोड करने के लिए उच्च गति पर मॉड्यूलेटेड प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को बदलकर, डेटा संचारित किया जाता है।
- रिसीवर के रूप में फोटोडिटेक्टर: फोटोडिटेक्टर से सुसज्जित उपकरण संशोधित प्रकाश संकेतों को प्राप्त करते हैं, तथा उन्हें विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर डेटा के रूप में संसाधित करते हैं।

लाभ:
- उच्च गति: Li-Fi कई Gbps की डेटा दर प्राप्त कर सकता है, जो पारंपरिक Wi-Fi से कहीं अधिक है।
- सुरक्षा: दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर कार्य करते हुए, Li-Fi दीवारों में प्रवेश नहीं करता है, जिससे छिपकर सुनने के विरुद्ध सुरक्षा बढ़ जाती है।
- कोई हस्तक्षेप नहीं: Li-Fi, Wi-Fi या सेलुलर नेटवर्क द्वारा उपयोग की जाने वाली रेडियो आवृत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
- ऊर्जा दक्षता: LED ऊर्जा-कुशल हैं, जो समग्र ऊर्जा बचत में योगदान देते हैं।

चुनौतियाँ और विचारणीय बातें:
- दृष्टि रेखा: ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच सीधी दृष्टि रेखा की आवश्यकता होती है।
- इनडोर उपयोग: कार्यालयों, अस्पतालों और स्मार्ट घरों जैसे इनडोर वातावरण के लिए आदर्श।
- एकीकरण: Li-Fi को मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपकरणों के साथ एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

अनुप्रयोग:
- इंटरनेट कनेक्टिविटी और इनडोर संचार: कार्यालयों, घरों और सार्वजनिक स्थानों में उच्च गति की इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है।
- सुरक्षित वातावरण: सैन्य ठिकानों, अस्पतालों और डेटा केंद्रों के लिए फायदेमंद ।
- पानी के अन्दर संचार: पानी के अन्दर संचार के लिए प्रभावी, जहां RF सिग्नल अप्रभावी होते हैं।

7. प्रदूषण के स्तर में वृद्धि से स्वच्छ हवा वाले शहरों में मृत्यु दर बढ़ सकती है: अध्ययन - द हिंदू

प्रासंगिकता : संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- वायु प्रदूषण

समाचार:
- जिन भारतीय शहरों में हवा साफ है, वहां वायु प्रदूषण बढ़ने से मृत्यु दर उन शहरों की तुलना में अधिक हो सकती है जहां प्रदूषण का भार अधिक है

मुख्य बिंदु :

- उदाहरण के लिए, बेंगलुरू में वायु प्रदूषण में समान वृद्धि, दिल्ली की तुलना में मृत्यु दर में अधिक वृद्धि कर सकती है, जहां वायु प्रदूषण का पृष्ठभूमि स्तर काफी अधिक है।
- कुल मिलाकर, हालांकि, जिन शहरों में प्रदूषण अधिक था, वहां वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वार्षिक मौतों का अनुपात अधिक था, दिल्ली में 11.5% वार्षिक मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती थीं, तथा बेंगलुरु में 4.8% मौतें होती थीं।
- दिल्ली की आबादी को प्रतिदिन वायु प्रदूषण का सामना औसत दिल्ली निवासी की तुलना में 30% अधिक करना पड़ता है।
- वैज्ञानिकों ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी के प्रदूषण और मृत्यु रजिस्ट्री आंकड़ों का विश्लेषण किया।
- लगभग 30,000 मौतें, या 10 शहरों में वार्षिक मौतों का 7.2%, अल्पकालिक PM 2.5 के कारण हुईं।
- अध्ययन में पाया गया कि इन शहरों में दो दिन की अवधि में PM 2.5 के औसत स्तर में प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि के कारण कुल दैनिक मृत्यु दर में 1.42% की वृद्धि हुई।

8. स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक बढ़ाया - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- स्मार्ट सिटी मिशन

समाचार:
- केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है।

मुख्य बिंदु:
- जून 2015 में शुरू की गई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया गया था।
- मिशन में देश के चयनित शहरों के कुछ क्षेत्रों को क्षेत्र विकास योजना के आधार पर मॉडल क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका शहर के अन्य भागों तथा निकटवर्ती शहरों और कस्बों पर भी प्रभाव पड़ने की आशा है।
- मिशन को कुछ राज्यों/शहरी सरकारों के प्रतिनिधियों से शेष 10% परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ और समय देने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।
- शेष चल रही परियोजनाएं कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं तथा विभिन्न जमीनी परिस्थितियों के कारण इनमें देरी हो रही है।
- इस विस्तार के बारे में शहरों को सूचित कर दिया गया है कि यह मिशन के अंतर्गत पहले से स्वीकृत वित्तीय आवंटन के अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना होगा।
- अब सभी चालू परियोजनाओं के 31 मार्च 2025 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

9. पेट्रोरसायन की औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के विकास में भूमिका – द मिंट

प्रासंगिकता:
जीएस III – बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे

परिचय:
- भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र देश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसने पिछले सात दशकों में क्षमता और मूल्य वृद्धि में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। घरेलू स्तर पर 80,000 से अधिक प्रकार के रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन किया जाता है, इस उद्योग में दो मिलियन से अधिक लोग काम करते हैं। भारत विशेष रसायनों, विशिष्ट कृषि रसायनों, रंगों और पिगमेंट के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश के अवसर हैं। हाल ही में, भारत वैश्विक बाजार में एक प्रतिस्पर्धी, उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, जिसने पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित किया है। वर्तमान में $178 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य वाले भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के वर्ष 2025 तक लगभग $300 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँचने का अनुमान है। वैश्विक रसायन और

पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को महामारी के कारण अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लानी पड़ी है , और भारत खुद को अनुकूल निवेश नीतियों के साथ एक आकर्षक क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करता है।

- रासायनिक और पेट्रोकेमिकल (CPC) उद्योग के उत्पादन और बिक्री में एशिया की बढ़ती भूमिका के कारण भारत एक महत्वपूर्ण संभावित निवेश क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। यह क्षेत्र भारत के विनिर्माण उद्योग और आर्थिक विकास का अभिन्न अंग है, जो कृषि, खाद्य और पेय पदार्थ, कपड़ा, रबर और पेट्रोलियम शोधन जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को परिष्कृत करने से प्राप्त पेट्रोकेमिकल्स में पॉलिमर, सिंथेटिक फाइबर , प्रदर्शन प्लास्टिक और बहुत कुछ शामिल हैं।

बाजार का आकार और वैश्विक स्थिति:

- इस उद्योग का मूल्य 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, तथा अनुमान है कि वर्ष 2025 तक इसका मूल्य लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।
- भारत विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी और उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है।
- महामारी ने वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत एक महत्वपूर्ण संभावित निवेश क्षेत्र के रूप में सामने आया है।
- भारत का रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

एकीकरण और आर्थिक योगदान:

- यह उद्योग भारत के विनिर्माण क्षेत्र और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह कृषि, खाद्य एवं पेय पदार्थ, वस्त्र, रबर और पेट्रोलियम शोधन जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से बुनियादी जरूरतों को पूरा करके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

विविध अनुप्रयोग:

- पेट्रो रसायन पॉलिमर, सिंथेटिक फाइबर , प्रदर्शन प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं।
- कृषि में, वे उर्वरकों और कीटनाशकों के निर्माण तथा फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) के लिए पेट्रोरसायनों पर निर्भर करता है।
- मोटर वाहन उद्योग टायरों और विभिन्न प्लास्टिक घटकों में सिंथेटिक रबर के लिए पेट्रोरसायनों का उपयोग करता है।
- पैकेजिंग उद्योग पेट्रोरसायनों को उनकी बहुमुखी प्रतिभा, स्थायित्व और लागत प्रभावशीलता के लिए महत्व देता है।
- कपड़ा और उपभोक्ता वस्तु उद्योग सिंथेटिक फाइबर और सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जिससे फैशन और घरेलू उत्पादों में क्रांति आती है।

ग्रोथ ड्राइवर्स :

- संबद्ध उद्योगों और प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं की ओर से पर्याप्त घरेलू मांग है।
- अनुकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने निर्यात मांग को बढ़ा दिया है, जिससे भारत विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।
- मजबूत सरकारी नीतियां उद्योग के विकास को समर्थन देती हैं, जैसे स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI (कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर)।
- अनुसंधान एवं विकास में निवेश में वृद्धि से हरित प्रौद्योगिकियों और नवीन उत्पादों के सृजन को बढ़ावा मिलता है।

पर्यावरण एवं स्थिरता चुनौतियाँ:

- जीवाश्म ईंधनों का निष्कर्षण और प्रसंस्करण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, प्रदूषण और आवास विनाश में योगदान देता है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा बन गया है, जिससे टिकाऊ तरीकों और वैकल्पिक सामग्रियों के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

आगे की राह:

- हरित रसायन और जैव-आधारित फीडस्टॉक्स को अपनाने से पेट्रोकेमिकल उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- रासायनिक रीसाइक्लिंग जैसी रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में प्रगति से प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद मिल सकती है।
- वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाने से, जहां सामग्रियों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है, अधिक सतत संसाधन प्रबंधन हो सकता है।

- सरकारों को उद्योग को स्थिरता की ओर ले जाने के लिए कड़े पर्यावरणीय नियम लागू करने की आवश्यकता है।
- हरित प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर्यावरण अनुकूल विकल्पों और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सुगम बना सकती है।
- वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और विश्व आर्थिक मंच जैसे संगठन संवाद और कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष:

- भारतीय रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग आधुनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न उद्योगों का समर्थन करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। उद्योग को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और स्थिरता चुनौतियों का सामना करना होगा। नवाचार, संधारणीय गतिविधियों और मजबूत नीतिगत फ्रेमवर्क को अपनाना उद्योग के भविष्य की कुंजी है। भारत मजबूत सरकारी समर्थन और वैश्विक मान्यता के साथ पेट्रोकेमिकल उद्योग में वैश्विक नेता बनने के लिए तैयार है। नवाचार, संधारणीय गतिविधियों और अनुकूल नीतियों में रणनीतिक निवेश आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए एक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करेगा।

10. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 816 मिलियन डॉलर बढ़कर 653.7 बिलियन डॉलर हुआ – इकोनॉमिक टाइम्स

प्रासंगिकता:

जीएस III – भारतीय अर्थव्यवस्था

परिचय:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, देश की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (FCA), जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है, रिपोर्ट किए गए सप्ताह में $3.773 बिलियन बढ़कर $576.337 बिलियन पर पहुँच गई। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण भंडार में $481 मिलियन की वृद्धि देखी गई, जिससे कुल भंडार $56.982 बिलियन पर पहुँच गया। विशेष आहरण अधिकार (SDR) में $43 मिलियन की वृद्धि हुई, जो $18.161 बिलियन पर पहुँच गया, और इस अवधि के दौरान IMF के साथ भारत की आरक्षित स्थिति $10 मिलियन बढ़कर $4.336 बिलियन हो गई।

वृद्धि में योगदान देने वाले कारक:

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ: विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक FCA $3.773 बिलियन बढ़कर $576.337 बिलियन हो गया। इस वृद्धि का श्रेय मजबूत निर्यात प्रदर्शन, मजबूत प्रेषण और रणनीतिक विदेशी निवेश को जाता है।
- स्वर्ण भंडार: भारत का स्वर्ण भंडार 481 मिलियन डॉलर बढ़कर 56.982 बिलियन डॉलर हो गया, जो RBI द्वारा रणनीतिक खरीद और अनुकूल वैश्विक स्वर्ण कीमतों के कारण हुआ, जो मुद्रा में उतार-चढ़ाव के खिलाफ बचाव रणनीति को दर्शाता है।
- विशेष आहरण अधिकार: SDR में 43 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई तथा यह 18.161 बिलियन डॉलर हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ जुड़ने तथा अपने वित्तीय संसाधनों का अनुकूलन करने में भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- IMF रिजर्व स्थिति: IMF के साथ भारत की रिजर्व स्थिति 10 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.336 बिलियन डॉलर हो गई, जो IMF के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने और एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल सुनिश्चित करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- आर्थिक स्थिरता: उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी आर्थिक झटकों, जैसे अचानक पूंजी बहिर्वाह या तेल की कीमतों में उछाल के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता और लचीलापन बढ़ता है।
- क्रेडिट रेटिंग: बेहतर विदेशी मुद्रा भंडार भारत की क्रेडिट रेटिंग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे सरकार और निगमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से उधार लेना आसान और सस्ता हो जाता है, जिससे उधार की शर्तें अधिक अनुकूल हो जाती हैं और ब्याज दरें कम हो जाती हैं।
- निवेशकों का भरोसा: एक मजबूत रिजर्व स्थिति निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है, अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। यह एक स्थिर और मजबूत आर्थिक माहौल का संकेत देता है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशों को प्रोत्साहित करता है।

- विनिमय दर प्रबंधन: पर्याप्त भंडार के साथ, RBI प्रभावी रूप से विनिमय दर का प्रबंधन कर सकता है, अत्यधिक अस्थिरता को रोक सकता है और एक स्थिर समष्टि आर्थिक वातावरण सुनिश्चित कर सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में लगे व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है।
- व्यापार सुविधा: उच्च भंडार यह सुनिश्चित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है कि देश अपने आयात दायित्वों को पूरा कर सके और बिना किसी व्यवधान के व्यापार संबंधों को बनाए रख सके, जो विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जो तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर करता है।

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का महत्व:

- आर्थिक लचीलापन: बढ़ता हुआ भंडार एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था को दर्शाता है जो वैश्विक वित्तीय उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी को झेलने में सक्षम है, तथा आर्थिक संकट के समय सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- उन्नत वैश्विक प्रतिष्ठा: विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च स्तर वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, जो मजबूत आर्थिक बुनियादी बातों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है, जिससे देश वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाता है।
- राजकोषीय और मौद्रिक स्थिरता: बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार सरकार और RBI द्वारा कार्यान्वित प्रभावी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का संकेत देता है, जो बाहरी ऋण का प्रबंधन करने और भुगतान का स्वस्थ संतुलन बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।
- मुद्रा में विश्वास: बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार भारतीय रुपये और इसकी स्थिरता में विश्वास को दर्शाता है, जिससे मुद्रा मूल्यह्रास का जोखिम कम होता है और RBI को स्थिर विनिमय दर बनाए रखने में सहायता मिलती है।

आगे की राह:

- निर्यात में विविधता: विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और निर्यात आधार में विविधता लाने से विदेशी मुद्रा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना फायदेमंद हो सकता है।
- FDI प्रवाह को मजबूत करना: निरंतर आर्थिक सुधार और व्यापार करने में आसानी में सुधार से अधिक FDI आकर्षित हो सकता है। बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है।
- धन प्रेषण चैनलों को बढ़ाना: प्रवासी भारतीयों के लिए अधिक सुगम और अधिक लागत प्रभावी धन प्रेषण चैनलों की सुविधा प्रदान करके धन प्रेषण के प्रवाह को बनाए रखा जा सकता है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लेन-देन की लागत को कम करने से अधिक धन प्रेषण को बढ़ावा मिल सकता है।
- विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन: राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और बाहरी ऋण का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना यह सुनिश्चित करेगा कि भंडार का इष्टतम और स्थायी रूप से उपयोग किया जाए। राजकोषीय घाटे को कम करना और सार्वजनिक वित्त का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना आवश्यक कदम हैं।
- आर्थिक लचीलापन बनाना: प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे आर्थिक लचीलापन बनाने वाले क्षेत्रों में निवेश करने से वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

- भारत का रिकॉर्ड-उच्च विदेशी मुद्रा भंडार देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद और रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। यह उपलब्धि बाहरी शॉक के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है और वैश्विक स्तर पर देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाती है। हालाँकि, इस गति को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में विविधता लाने, निवेश आकर्षित करने और संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। सामरिक दृष्टिकोण के साथ, भारत दीर्घकालिक आर्थिक विकास, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का लाभ उठा सकता है। आगे की यात्रा अवसरों से भरी हुई है, और सही नीतियों और कार्यों के साथ, भारत एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रख सकता है।

11. RBI का अधिशेष: खर्च करें या न करें - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाव, विकास, प्रगति और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
प्रसंग:

- अप्रत्याशित घटनाक्रम में, RBI ने पिछले महीने घोषणा की कि वह सरकार को एक बड़ा लाभांश हस्तांतरित कर रहा है, जो कि अनुमान से कहीं अधिक है।

- इससे इस बात पर काफी चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार इस अप्रत्याशित धनराशि को किस प्रकार खर्च कर सकती है।

सरकारी खर्च

- राजकोषीय प्रबंधन दो सामान्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
- सबसे पहले, घाटे को विवेकपूर्ण स्तर पर रखा जाना चाहिए।
  - भारत में, लंबे समय से चले आ रहे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के अनुसार, यह स्तर आदर्श रूप से केंद्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन प्रतिशत होना चाहिए।
- दूसरा, जब अर्थव्यवस्था खराब चल रही हो तो सरकारों को इस मानक से थोड़ा अधिक खर्च करना चाहिए और जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही हो तो थोड़ा कम खर्च करना चाहिए।
- दूसरे सिद्धांत के अनुसार घाटे में परिवर्तन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है।
- बुरे समय में, जब निजी क्षेत्र की मांग गिर रही हो, तो सरकार को आगे आकर अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मांग को बढ़ावा देना चाहिए।
- जब अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगता है तो आवश्यकताएं उलट जाती हैं।
- जैसे-जैसे निजी मांग पुनर्जीवित हो रही है, सरकार को अपने खर्च में कटौती करने की आवश्यकता है, अन्यथा समग्र मांग आपूर्ति से आगे निकल जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा।

घाटे को कम करने में असमर्थता

- सामान्य से अधिक घाटे के बाद सामान्य से कम घाटा भी जरूरी है, ताकि सरकारी ऋण ऊपर की ओर बढ़ने के बजाय स्थिर हो जाए।
- इन दो सिद्धांतों का पालन करने से देश को ऋण समस्याओं से दूर रखा जा सकता है, साथ ही विकास चक्र के उतार-चढ़ाव को भी स्थिर रखा जा सकता है।
- हालाँकि, भारत में सरकारें हमेशा ही अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करने में संघर्ष करती रही हैं, चाहे अर्थव्यवस्था धीमी हो या तेजी से बढ़ रही हो।
- वर्ष 2000-01 से वर्ष 2019-20 तक की 20 वर्ष की अवधि में, केंद्र का औसत राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत था, जो FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य से काफी अधिक था।
- महामारी के दौरान, वर्ष 2020-21 में घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो एक बड़ी वृद्धि थी, लेकिन अर्थव्यवस्था को लगे झटके के आकार को देखते हुए यह उचित वृद्धि थी।
- लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद भी घाटा कम होने की गति धीमी रही है।
- इस वर्ष की शुरुआत में पेश अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार वर्ष 2024-25 के लिए 5.1 प्रतिशत घाटे का लक्ष्य रख रही है।
  - महामारी समाप्त होने के तीन वर्ष बाद भी घाटा महामारी-पूर्व स्तर से अधिक है, तथा FRBM मानदंड के कहीं भी करीब नहीं है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों का समेकित घाटा अब सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.5-9 प्रतिशत है (FRBM अधिनियम द्वारा अनुशंसित 6 प्रतिशत की तुलना में)।

सुझावात्मक उपाय

- कुछ टिप्पणीकारों के अनुसार, सरकार को अपना पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़ाना चाहिए।
- अंतरिम बजट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर धीमी हो जाएगी।
- लेकिन अब इस अधिशेष लाभांश के साथ, सरकार अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकती है। यह एक गलती होगी।
- उदाहरण के लिए, चीन ने अपने बुनियादी ढांचे के निर्माण के तहत एक ही शहर में दो से तीन हवाई अड्डे बना लिए और अब वह इन परियोजनाओं के लिए लिए गए ऋण को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- सरकारें दो कारणों से पूंजीगत व्यय करती हैं: विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए।
- भारत में बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से एक समस्या है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है। लेकिन एक साथ नहीं।
- महामारी के बाद से, सरकार का पूंजीगत व्यय औसतन 30 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।
- विकास के लिए सभी पूंजीगत व्यय आवश्यक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, दूरसंचार MTNL और BSNL को पुनर्जीवित करने के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये का उपयोग करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, खासकर तब जब पूरे देश में निजी ऑपरेटरों द्वारा सस्ती सेल फोन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- इसी तरह, यह भी स्पष्ट नहीं है कि बुलेट ट्रेनों पर लाखों करोड़ रुपये खर्च करना उस देश में उचित ठहराया जा सकता है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2,500 डॉलर से भी कम है।

फैक्ट फटाफट

1. भारत ने कोलंबो प्रक्रिया के तहत अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत कीं – इकोनॉमिक टाइम्स4

प्रसंग:

- भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता की है।

कोलंबो प्रक्रिया

- यह 12 एशियाई सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है जो विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम गतिविधियों को साझा करता है। इसके सदस्यों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। गैर-बाध्यकारी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) कोलंबो प्रक्रिया के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

कोलंबो प्रक्रिया के उद्देश्य:

- प्रवासी श्रमिकों का संरक्षण: रोजगार और प्रवास में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना।
- नियामक तंत्र: पारदर्शी, निष्पक्ष और कुशल भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- प्रवासन शासन: प्रवासन प्रबंधन और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण में सुधार करना।
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते: श्रम प्रवास पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को सुगम बनाना।
- धन प्रेषण और निवेश: प्रवासी समुदायों द्वारा धन प्रेषण और निवेश के माध्यम से प्रवास के विकास प्रभाव को बढ़ावा देना।

मुख्य पहल:

- भर्ती गतिविधियों का विनियमन: नैतिक भर्ती को बढ़ाना और शोषण को कम करना।
- कौशल विकास एवं मान्यता: प्रवासी श्रमिकों के लिए कौशल एवं योग्यता मान्यता में सुधार करना।
- सामाजिक संरक्षण और कल्याण: प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक संरक्षण और कल्याण तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- प्रस्थान पूर्व अभिविन्यास और सूचना: प्रस्थान से पहले प्रवासियों को सटीक सूचना और अभिविन्यास प्रदान करना।
- द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग: प्रवासन मुद्दों पर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना।

कोलंबो प्रक्रिया के लाभ:

- सहयोगात्मक दृष्टिकोण: यह सदस्य देशों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रवासी श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होता है।
- नीति सामंजस्य: प्रवासन प्रबंधन पर नीति सामंजस्य और संरेखण को सुगम बनाता है।
- क्षमता निर्माण: सदस्य राज्यों के बीच क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण को बढ़ाता है।
- वकालत: क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत के लिए एक मंच प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

- कोलंबो प्रक्रिया एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. मेगाफौना: आंध्र प्रदेश में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला मिला

- पुरातत्वविदों ने आंध्र प्रदेश में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है, जो भारत में मेगाफौना के विलुप्त होने के पैटर्न पर प्रकाश डालता है।
- मेगाफौना, जो आम तौर पर 50 किलोग्राम से अधिक वजन वाले जानवरों को संदर्भित करता है, में विशाल सर्वाहारी शुतुरमुर्ग शामिल है। यह खोज भारत में मेगाफौना विलुप्त होने के कारणों पर शोध को बल देती है, जिसमें लगभग 30,000 साल पहले मनुष्यों के आगमन और सह-विकास परिकल्पना जैसे कारकों पर प्रकाश डाला गया है, जो यह मानता है कि भौगोलिक अलगाव और अजैविक तत्वों ने उनके विलुप्त होने में तेजी लाई।

प्रीलिम्स ट्रैक

Q.1 कावेरी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?

A. कर्नाटक
B. तमिलनाडु
C. केरल
D. आंध्र प्रदेश

Q 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सांभर हिरण केवल ब्रह्मपुत्र और दिबांग नदियों के बीच के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
2. इसे IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

Q 3. 'वरुण-23' किनके बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है?

A. भारत और नेपाल
B. भारत और फ्रांस
C. भारत और श्रीलंका
D. भारत और जापान

Q 4. 'ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल' क्या है?

A. यह सरकार और व्यापार जगत के नेताओं के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मात्रा निर्धारित करने और प्रबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखा उपकरण है
B. यह संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है, जिसके तहत विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
C. यह वर्ष 2022 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को निर्दिष्ट स्तर तक कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित एक अंतर-सरकारी समझौता है।
D. यह विश्व बैंक द्वारा आयोजित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है

Q 5. 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह नीति आयोग का एक अंग है।
2. इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है।
3. यह अर्थव्यवस्था के वृहद-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q 6. **समुद्र तल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. मध्य महासागरीय कटकों पर ज्वालामुखी विस्फोट आम बात है।
2. शिखर से दूर जाने पर चट्टानों की आयु घटती जाती है।
3. महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत नई हैं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q7. **थर्मोस्फीयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. थर्मोस्फेयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से घटता है।
2. पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित हो जाती हैं।
3. अंतरिक्ष शटल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दोनों पृथ्वी की परिक्रमा थर्मोस्फीयर के भीतर करते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q 8. **मत्स्य उत्पादन और पकड़ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ अच्छी हैं?**

1. ठंडे क्षेत्रों में उथली महाद्वीपीय शैलियाँ
2. फाइटोप्लांकटन की प्रचुरता
3. गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन
4. पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी का तटीय क्षेत्र में ऊपर उठना

Q 9 **महासागर में सुनामी लहरों की गति काफी समय तक किस पर निर्भर करती है?**

A. महासागर की गहराई
B. मध्य महासागरीय कटकों से दूरी
C. तरंग के स्रोत से दूरी
D. पानी का घनत्व

Q 10. **उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ हैं?**

1. क्षोभमंडल में अस्थिर स्थिति
2. प्रबल कोरिओलिस बल
3. तेज़ ऊर्ध्वाधर हवा
4. गर्म और नम हवा की बड़ी और निरंतर आपूर्ति।

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प A सही है

व्याख्या :

- कावेरी वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक के मांड्या, चामराजनगर और रामनगर जिलों में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है।

उत्तर : 2 विकल्प B सही है

व्याख्या :

- भारत में उपस्थिति: सांभर हिरण भारत के लगभग हर कोने में पाया जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से मध्य भारत में पाया जाता है। इन्हें कान्हा, कॉर्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, गिर, दुधवा, मानस, काजीरंगा और सरिस्का में आसानी से देखा जा सकता है।
- भीषण शिकार, स्थानीय उग्रवाद और आवास के औद्योगिक दोहन के कारण इसे 2008 से IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

उत्तर : 3 विकल्प B सही है

व्याख्या :

- संदर्भ: भारत-फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'वरुण-23' का 21वां संस्करण अरब सागर में हुआ। इस अभ्यास में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, एक टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे।
- उनके अभ्यास का इतिहास बहुत पुराना है, जो 1993 से शुरू हुआ है, और यह भारत-फ्रांस के मजबूत रणनीतिक संबंधों का प्रतीक बन गया है, जो समुद्री सुरक्षा में सीखने और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- भारत और फ्रांस के बीच अन्य रक्षा अभ्यास:
- वरुण – नौसैनिक अभ्यास
- डेजर्ट नाइट-21 और गरुड़ (वायु अभ्यास)
- शक्ति – सेना अभ्यास

उत्तर : 4 विकल्प A सही है

व्याख्या :

- ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल (GHG प्रोटोकॉल) सरकार और व्यापार जगत के नेताओं के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मात्रा निर्धारित करने और प्रबंधित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन उपकरण है।
- यह विश्व संसाधन संस्थान (WRI) और सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद (WBCSD) के बीच एक दशक पुरानी साझेदारी है।
- यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्वसनीय और प्रभावी कार्यक्रमों की एक नई पीढ़ी बनाने के लिए दुनिया भर के व्यवसायों, सरकारों और पर्यावरण समूहों के साथ काम कर रहा है।

उत्तर : 5 विकल्प B सही है

व्याख्या :

- कथन 1: वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) को दिसंबर 2010 में शीर्ष स्तरीय मंच के रूप में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था (नीति आयोग की स्थापना से बहुत पहले)। इसलिए, 1 गलत है।
- कथन 2: परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं और इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA, IRDA और FMC) के प्रमुख, वित्त सचिव और/या सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं। इसलिए, 2 सही है।
- कथन 3: विनियामकों की स्वायत्तता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, परिषद अर्थव्यवस्था की व्यापक विवेकपूर्ण निगरानी करती है, जिसमें बड़े वित्तीय समूहों का कामकाज भी शामिल है, और अंतर-विनियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र विकास के मुद्दों को संबोधित करती है। इसलिए, कथन 3 सही है।
- यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

उत्तर : 6 विकल्प B सही है

व्याख्या

- कथन 2 गलत है।
- समुद्र तल फैलाव को इन परिघटनाओं का उपयोग करके सत्यापित किया जाता है:
- यह महसूस किया गया कि मध्य-महासागरीय कटकों के साथ-साथ ज्वालामुखी विस्फोट आम बात है और वे इस क्षेत्र में सतह पर भारी मात्रा में लावा लाते हैं। समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली है।
- शिखर से दूर जाने पर चट्टानों की आयु बढ़ती जाती है।
- महासागरीय चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत नई हैं।
- समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली है।
- गहरी खाइयों में भूकंप की घटनाएं अधिक गहराई में होती हैं, जबकि मध्य महासागरीय रिज क्षेत्रों में भूकंप के केंद्र कम गहराई पर होते हैं।

उत्तर : 7 विकल्प B सही है

व्याख्या

- कथन 1 ग़लत है.
- थर्मोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के ठीक ऊपर और एक्सोस्फीयर के नीचे है। यह हमारे ग्रह से लगभग 90 किलोमीटर से लेकर 500 से 1,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है।
- यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। दरअसल, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत द्वारा परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं।
- अंतरिक्ष यान और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दोनों पृथ्वी की परिक्रमा थर्मोस्फीयर के भीतर करते हैं! यहीं पर आपको पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रह भी मिलेंगे।
- इसे थर्मोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां तापमान 1,500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि, उच्च तापमान के बावजूद, दबाव बहुत कम होता है, इसलिए उपग्रहों को गर्मी से नुकसान नहीं होता है।

उत्तर : 8 विकल्प D सही है

व्याख्या

- **मत्स्य उत्पादन एवं पकड़ के लिए निम्नलिखित स्थितियाँ अच्छी हैं:**
- पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी का तटीय क्षेत्र में ऊपर उठना
- फाइटोप्लांकटन की प्रचुरता
- गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन
- ठंडे क्षेत्रों में उथली महाद्वीपीय शैलियाँ

उत्तर : 9 विकल्प A सही है

व्याख्या

- सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं। समुद्र की गहराई में, सुनामी लहरों की ऊँचाई में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जैसे-जैसे लहरें अंतर्देशीय यात्रा करती हैं, वे समुद्र की गहराई कम होने के साथ-साथ अधिक से अधिक ऊँचाई तक पहुँचती जाती हैं।
- यह लहर के स्रोत से दूरी के बजाय महासागर की गहराई पर निर्भर करता है। सुनामी लहरें गहरे पानी में जेट विमानों की तरह तेज़ गति से यात्रा कर सकती हैं, लेकिन उथले पानी में पहुँचने पर धीमी हो जाती हैं।

उत्तर : 10 विकल्प B सही है

व्याख्या

- **उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए कुछ प्रारंभिक स्थितियाँ हैं:**
- (i) गर्म और नम हवा की बड़ी और निरंतर आपूर्ति जो भारी मात्रा में गुप्त ऊष्मा मुक्त कर सकती है।
- (ii) मजबूत कोरिओलिस बल जो केंद्र में कम दबाव को भरने से रोक सकता है (भूमध्य रेखा के पास कोरिओलिस बल की अनुपस्थिति 0°-5° अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय चक्रवात के गठन को रोकती है)।
- (iii) क्षोभमंडल में अस्थिर स्थिति जो स्थानीय क्रियाएं पैदा करती है जिसके आसपास चक्रवात विकसित होता है।
- (iv) अंत में, मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह की अनुपस्थिति, जो गुप्त ऊष्मा के ऊर्ध्वाधर परिवहन को बाधित करती है।

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com